

गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD, SURAT, LUCKNOW

वर्ष : 16
अंक : 193
दि. 14.11.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा
AHMEDABAD EDITION

माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी गड़बड़ी से वैश्विक कामकाज प्रभावित, 74 देशों में मचा हड़कंप

नई दिल्ली। दुनिया की प्रमुख तकनीकी कंपनियों में शामिल माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन सेवाओं में आई बड़ी तकनीकी खराबी ने वैश्विक स्तर पर सरकारी और निजी क्षेत्र के कामकाज को प्रभावित कर दिया। गलत सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण कंपनी की कई प्रमुख सेवाओं में व्यवधान आया, जिससे 74 देशों के यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। ईमेल, ऑनलाइन मीटिंग, फाइल शेयरिंग और कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल टूल प्रभावित होने से सरकारी दफ्तरों, बैंकों, अस्पतालों, स्कूलों और विमानन सेवाओं तक पर असर दिखाई दिया। भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा और स्पाइसजेट को दिल्ली से संचालित होने वाली तीन उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि कुछ अन्य उड़ानों में देरी हुई। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस और खुफिया एजेंसियों, हॉन्गकॉन्ग में बैंकिंग सेवाओं तथा जापान में सरकारी प्रणालियों के प्रभावित होने की खबरें सामने आईं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह किसी साइबर हमले या हैकिंग का मामला नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर अपडेट से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी है। हालांकि, शुरुआती सुधार प्रयास सफल नहीं होने के कारण समस्या लंबी खिंच गई और 24 घंटे से अधिक समय तक यूजर्स को परेशानी झेलनी पड़ी।



माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में व्यवधान का असर उसके व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम पर पड़ा। ईमेल के लिए इस्तेमाल होने वाला आउटलुक, ऑनलाइन मीटिंग और बातचीत का प्लेटफॉर्म टीम्स, फाइलों को साझा करने और सुरक्षित रखने की सुविधा देने वाला शेयरपॉइंट ऑनलाइन तथा एआई आधारित टूल कोपायलट 365 प्रभावित हुए। इसके अलावा एक्सचेंज ऑनलाइन, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर और प्लानर जैसी सेवाओं में भी दिक्कतें सामने आईं। इन सेवाओं का इस्तेमाल दुनियाभर में लाखों संस्थान अपने दैनिक कामकाज के लिए करते हैं। ऐसे में तकनीकी खराबी का असर केवल व्यक्तिगत यूजर्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई कंपनियों और संस्थानों की आंतरिक कार्यप्रणाली भी प्रभावित हुई। यूजर्स ने ईमेल भेजने और प्राप्त करने, ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होने, जरूरी दस्तावेज खोलने, फाइल सेव करने तथा कार्यालयों के साझा डेटा तक पहुंचने में परेशानी की शिकायत की। कई कर्मचारियों के लिए अपने सहकर्मियों से संपर्क करना और निर्धारित समय पर काम पूरा करना मुश्किल हो गया। जिन संस्थानों का कामकाज पूरी तरह माइक्रोसॉफ्ट 365 के डिजिटल टूल पर निर्भर है, उन्हें सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि, कंपनी की सभी सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं हुई थीं। अलग-अलग क्षेत्रों और यूजर्स पर इसका प्रभाव अलग-अलग रहा। जिन संस्थानों ने माइक्रोसॉफ्ट की प्रभावित सेवाओं का इस्तेमाल नहीं किया, उनका कामकाज सामान्य रूप से जारी रहा।

कंपनी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रभावित बुनियादी ढांचे के कुछ हिस्सों की मरम्मत पूरी कर ली गई है। इसके बाद इस क्षेत्र में सेवाओं का ट्रैफिक धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी टीमें समस्या के मूल कारण को दूर करने और प्रभावित यूजर्स को दोबारा सेवाओं से जोड़ने में जुटी रहीं। कंपनी के सामने चुनौती यह भी थी कि सुधार के दौरान सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव न पड़े और सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से सामान्य किया जा सके।

भारत में इस तकनीकी खराबी का असर विमानन क्षेत्र पर भी देखने को मिला। शुक्रवार सुबह स्पाइसजेट ने दिल्ली से पुणे, लेह और मुंबई जाने वाली तीन उड़ानें रद्द कर दीं। इसके अलावा दरभंगा और मुंबई जाने वाली दो अन्य उड़ानों के संचालन में देरी हुई। उड़ानों के रद्द होने और समय में बदलाव से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ा, जबकि कुछ को एयरपोर्ट पर उड़ान से संबंधित नई जानकारी का इंतजार करना पड़ा। स्थिति को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए सलाह जारी की। यात्रियों से कहा गया कि वे घर से निकलने से पहले संबंधित एयरलाइन की वेबसाइट या अन्य आधिकारिक माध्यमों से अपनी उड़ान की ताजा स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें। इंडिगो और अकासा एयरलाइंस ने भी यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर संभावित तकनीकी व्यवधान को ध्यान में रखते हुए यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जांचने की सलाह दी। वहीं एयर इंडिया ने कहा कि उसकी उड़ानें इस समस्या से प्रभावित नहीं हुईं। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने ईमेल ट्रैफिक को कुछ समय के लिए वैकल्पिक रास्ते से भेजने की व्यवस्था की थी, ताकि परिचालन से जुड़े जरूरी संदेशों का आदान-प्रदान जारी रह सके।

भारत से बाहर भी इस तकनीकी समस्या का प्रभाव कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिखाई दिया। हॉन्गकॉन्ग में बैंकिंग सेवाओं से जुड़े काम प्रभावित हुए। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस और खुफिया एजेंसियों के कामकाज में व्यवधान की जानकारी सामने आई। जापान में सरकारी प्रणालियों तथा फिलीपींस में अदालतों के काम पर भी असर पड़ा। इसके अलावा कुछ स्थानों पर स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं और अस्पतालों की डिजिटल सेवाएं प्रभावित हुईं। सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में डिजिटल प्रणालियों का बढ़ता इस्तेमाल इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी एक बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्म में आई खराबी का असर कई अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंच सकता है।

आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में व्यवधान से संबंधित शिकायतें भारतीय समयानुसार गुरुवार, 12 नवंबर की रात करीब 9 बजकर 45 मिनट से दर्ज होनी शुरू हुईं। शुरुआत में शिकायतों की संख्या सीमित थी, लेकिन कुछ ही समय में तेजी से बढ़ने लगी। लगभग एक घंटे के भीतर इसका असर 74 देशों तक पहुंच गया। रात करीब 11 बजकर 30 मिनट तक आउटलुक को लेकर शिकायतों की संख्या 1.40 लाख से अधिक हो गई थी। यह सामान्य दिनों में दर्ज होने वाली शिकायतों की तुलना में लगभग 2,000 गुना ज्यादा बताई गई। शिकायतों में अचानक आई इस तेजी ने समस्या के व्यापक स्तर को उजागर कर दिया।

माइक्रोसॉफ्ट ने इस मामले में कहा कि यह किसी हैकर के हमले या साइबर अपराध की घटना नहीं है। कंपनी के अनुसार, गलत सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण तकनीकी समस्या पैदा हुई। इसे ठीक करने के लिए शुरुआती स्तर पर कुछ बदलाव किए गए, लेकिन वे उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रहे। इसके बाद कंपनी ने सुधार के दूसरे तरीकों पर काम शुरू किया। कंपनी की कोशिश थी कि प्रभावित यूजर्स को दोबारा सेवाओं से जोड़ा जाए, लेकिन ऐसा करते समय सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। तकनीकी सुधार की इसी प्रक्रिया के कारण सेवाओं को सामान्य होने में अधिक समय लगा।

इस घटना की तुलना जुलाई 2024 में हुए क्राउडस्ट्राइक आउटेज से भी की जाने लगी। उस समय एक खराब अपडेट के कारण दुनियाभर में बड़ी संख्या में विंडोज कंप्यूटर प्रभावित हुए थे और विमानन, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में कामकाज बाधित हुआ था। हालांकि, दोनों घटनाओं में तकनीकी गड़बड़ी का तरीका अलग हो सकता है। इसके बावजूद इन घटनाओं ने यह सवाल फिर खड़ा कर दिया है कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता के बीच किसी एक तकनीकी खराबी से कितने बड़े पैमाने पर कामकाज प्रभावित हो सकता है।

माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार, दुनिया में 43 करोड़ से अधिक लोग माइक्रोसॉफ्ट 365 के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 30 से 40 लाख कंपनियां अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए इन सेवाओं पर निर्भर हैं। फॉर्च्यून 500 की 90 फीसदी से अधिक कंपनियों में कोपायलट के इस्तेमाल का भी उल्लेख किया गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं अब केवल ईमेल या दस्तावेज तैयार करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कई कंपनियों की पूरी कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ट्रॉय हंट ने इस समस्या के व्यापक प्रभाव की ओर ध्यान दिलाया। उनके मुताबिक, कई अन्य ऑनलाइन सेवाएं भी ईमेल और वेरिफिकेशन से जुड़े कामों के लिए माइक्रोसॉफ्ट की प्रणालियों पर निर्भर रहती हैं।

बंगाल में 23 नवंबर को आएगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 16 जनवरी को अंतिम प्रकाशन

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को दुरुस्त और अद्यतन करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत 23 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद मतदाताओं को अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच करने तथा किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे ठीक कराने का अवसर मिलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में सुधार कराने के लिए दावे तथा आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इन दावों और आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तिथि आठ जनवरी 2027 निर्धारित की गई है, जबकि संशोधित और अंतिम मतदाता सूची 16 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से नए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के साथ ही पहले से दर्ज जानकारियों को भी सत्यापित किया जाएगा। इस बार पुनरीक्षण अभियान में उन युवाओं को भी मतदाता बनने का अवसर मिलेगा, जो एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। ऐसे युवा निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम किसी कारणवश मौजूदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, उन्हें भी नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा। चुनाव आयोग की इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। वहीं, जिन मतदाताओं के नाम, पते या अन्य विवरणों में गलती है, वे निर्धारित समय के भीतर सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया को आम लोगों के लिए आसान बनाने के उद्देश्य से विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए 28 और 29 नवंबर तथा पांच, छह, 12, 13, 19 और 20 दिसंबर की तारीखें निर्धारित की गई हैं। इन विशेष



शिविरों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे और मतदाताओं को आवेदन भरने, जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने तथा संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने में सहायता करेंगे। शिविरों के माध्यम से उन लोगों तक भी पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, जिन्हें ऑनलाइन या कार्यालय स्तर पर आवेदन करने में कठिनाई होती है। खासकर पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं और सूची में नाम छूट जाने वाले पात्र नागरिकों के लिए ये शिविर उपयोगी साबित हो सकते हैं।

पुनरीक्षण अभियान के दौरान केवल नए नाम जोड़ने और पुराने नाम हटाने तक ही प्रक्रिया सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक महत्वपूर्ण जानकारी की भी जांच की जाएगी। आयोग की ओर से मतदाताओं के नाम, पते, तस्वीरों और अन्य विवरणों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता का पूरा पता स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से दर्ज किया जाएगा। इसमें मकान संख्या, मंजिल, वार्ड, सड़क, मोहल्ला, गांव या शहर, जिला और पिन कोड जैसी जानकारियों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य मतदाता की सही पहचान सुनिश्चित करना और मतदान केंद्र से संबंधित किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति को दूर करना है।

चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों के निर्धारण और मतदाताओं के आवंटन को लेकर भी विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं। आयोग के मुताबिक, एक ही पते पर रहने वाले परिवार के सदस्यों को अलग-अलग मतदान केंद्रों में रखने से बचा जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, एक ही इमारत और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची के एक ही हिस्से में रखे जाएंगे। इससे मतदान के दिन मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी। साथ ही परिवार के सदस्यों को अलग-अलग केंद्रों पर जाने की परेशानी भी कम हो सकती है। इस दौरान मृत मतदाताओं के नाम हटाने और स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जा चुके लोगों की प्रविष्टियों की जांच भी की जाएगी। कई बार स्थान परिवर्तन, मृत्यु या अन्य कारणों से मतदाता सूची में पुराने नाम बने रह जाते हैं। इसके अलावा एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज होने की संभावना भी रहती है। आयोग ऐसे मामलों की पहचान कर आवश्यक सत्यापन के बाद उचित कार्रवाई करेगा। दोहरी प्रविष्टियों को हटाने और गलत जानकारी को दुरुस्त करने से मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। तस्वीरों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिन मतदाताओं की तस्वीरें अस्पष्ट, गलत या पहचान के लिहाज से अनुपयुक्त पाई जाएंगी, उनका सत्यापन कर आवश्यकतानुसार तस्वीरों को बदला जाएगा। इसका उद्देश्य मतदाता पहचान को अधिक विश्वसनीय बनाना है। आयोग की कोशिश है कि अंतिम सूची में प्रत्येक मतदाता का नाम और उससे संबंधित विवरण सही तरीके से दर्ज हो, ताकि मतदान के समय किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न आए। इस पूरी प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को पुनरीक्षण अभियान से जोड़ा जाएगा, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची की जांच कर सकें और आवश्यक दावे तथा आपत्तियां संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकें। बीएलए की भागीदारी से सूची में छूटे पात्र मतदाताओं, गलत प्रविष्टियों और अन्य विसंगतियों की पहचान में सहायता मिल सकती है।



संपादकीय

फिर दहशत की दस्तक

भारत विरोध को प्राणवायु बनाने वाले पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह भारत पर घात का कोई मौका चूकेगा। पाक प्रायोजित आतंक का चेहरा एक बार फिर जम्मू-कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमले में उजागर हुआ है। किश्तवाड़ में दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों यानी एसपीओ की हत्या और कुलगाम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की पोस्ट पर हमले की हालिया घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली हैं। करीब चौबीस घंटे के भीतर हुई ये घटनाएं बताती हैं कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा हालात अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं। ये घटनाएं एक बार फिर याद दिलाती हैं कि सामान्य स्थिति और स्थायी शांति के दावों से इतर इलाके में आतंकवाद के रक्तबीज मौजूद हैं। दुखद ही है कि लापता होने के एक दिन बाद दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों के गोलियों से छलनी शव बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सीआरपीएफ की चेकपोस्ट पर हुए हमले में तीन जवान घायल हुए हैं। निस्संदेह,यह हमारी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के लिये नई चुनौती है। उल्लेखनीय है कि इससे ठीक एक साल पहले राजधानी में लाल किले के पास एक कार धमाके में ग्यारह लोगों की जान चली गई थी। कालांतर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनएआई की व्यापक जांच के बाद पता चला था कि विस्फोट की घटना में जम्मू-कश्मीर स्थित पुलवामा के एक डॉक्टर की मुख्य भूमिका रही थी। बहरहाल, जम्मू-कश्मीर में हालिया आतंकी हमलों की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार के उस दावे पर सवाल उठाये हैं, जिसमें कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर आतंकवाद से मुक्त हो चुका है। ऐसे वक्त बयानबाजी से आगे बढ़कर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को प्रभावी बनाने, सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि स्थानीय समुदायों की चिंता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

निस्संदेह, आज के आधुनिक उन्नत तकनीक के युग में आतंकवाद से लड़ाई के लिये तमाम विकल्प सुरक्षा बलों के पास मौजूद हैं। लेकिन स्थानीय समाज में घुल-मिल कर रहने वाले आतंकियों तक पहुंच बनाने के लिये लोकल संपर्क सूत्रों की बड़ी भूमिका होती है। कोई भी केंद्रीय सत्ता स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने में असहजता महसूस करेगी। पाकिस्तानी सीमा से लगने वाले दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे बिना किसी भय व दबाव के सुरक्षा एजेंसियों से सहयोग करें। निस्संदेह, आतंकवाद को हराने के लिये उनकी सुरक्षा, उनका भरोसा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाये रखने के लिये कानून-व्यवस्था व शांति बनाये रखना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने देखा था कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी की आर्थिकी को भारी चोट पहुंची थी। जो अब धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी थी। देश के विभिन्न भागों व विदेशों से आने वाले पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने लौटने लगे थे। निर्विवाद रूप से किश्तवाड़ जैसे इलाकों में पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। लेकिन गाहे-बगाहे होने वाले आतंकी हमले व हिंसा पर्यटकों को दूर रख सकती है। इससे विकास की गति बाधित होती है और स्थानीय लोगों की आजीविका संकट में पड़ जाती है। भले ही अभी तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिल पाया हो, लेकिन इसके बावजूद घाटी के लोगों का भरोसा हासिल करना बेहद जरूरी है। खासकर स्थानीय लोगों को सीमा पार से पोषित आतंकवाद के खात्मे के साथ कानून-व्यवस्था में भरोसा दिलाना जरूरी है। इस केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों से निपटने और जनता का भरोसा फिर से बहाल करने के लिये ठोस और कारगर रणनीति की जरूरत है। इसमें दो राय नहीं कि सीमाओं की सुरक्षा करने और घुसपैठ को रोकने में सेना व सुरक्षा बलों ने काफी हद तक सफलता पायी है, लेकिन स्थानीय समाज में घुसपैठ करने वाले आतंकियों से निबटना अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

गर्म होती दुनिया में बढ़ते प्रदूषण से घुटती सांसों की चुनौती

> पिछले अनेक जलवायु सम्मेलनों में महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित हुए, लेकिन वास्तविक क्रियान्वयन की गति अपेक्षाकृत धीमी रही। आज आवश्यकता नए संकल्पों की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि पुराने संकल्पों को धरातल पर उतारने की है। विकसित देशों को वित्तीय दायित्वों को गंभीरता से लेना होगा।



आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की उस कठोर सच्चाई का सामना कर रही है, जिसे कभी भविष्य की आशंका समझा जाता था। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात, जंगलों की आग, समुद्र के बढ़ते जलस्तर और असामान्य गर्मी अब असाधारण घटनाएं नहीं रह गई हैं। प्रकृति का संतुलन जिस तेजी से बिगड़ रहा है, उसने मानव सभ्यता के सामने अस्तित्व का गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 9 नवंबर 2026 को जारी स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट 2026 रिपोर्ट इस संकट की भयावहता को वैज्ञानिक आंकड़ों के साथ सामने रखती है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 पिछले चार सबसे गर्म वर्षों में शामिल होने की राह पर है और जनवरी से सितंबर तक वैश्विक औसत तापमान 1850-1900 के पूर्व-औद्योगिक औसत से लगभग 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। 2015 से 2026 तक के सभी 12 वर्ष रिकॉर्ड के सबसे गर्म वर्ष रहे हैं। यह आंकड़ा केवल तापमान की वृद्धि का आंकड़ा नहीं है, बल्कि मानव जीवन के बढ़ते संकट का संकेत है। समुद्रों में जमा हो रही अतिरिक्त गर्मी, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ता समुद्र-स्तर, बढ़ता प्रदूषण और बदलता वर्षा चक्र आने वाले वर्षों की गंभीर चुनौतियों का संकेत दे रहे हैं। डब्ल्यूएमओ के अनुसार महासागर लगातार दसवें वर्ष रिकॉर्ड गर्मी की ओर हैं और 2026 में वैश्विक समुद्र-स्तर भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है।इस वर्ष की स्थिति इसलिए भी अधिक चिंताजनक है क्योंकि मजबूत अलनीनो विकसित हो रहा है। डब्ल्यूएमओ के अनुसार अगस्त से अलनीनो तेजी से मजबूत हुआ है और नवंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच इसकी तीव्रता असाधारण स्तर तक पहुंच सकती है। इसके कारण 2027 में अत्यधिक गर्मी, सूखा और भारी वर्षा जैसी चरम मौसमी घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। अर्थात खतरा केवल आज का नहीं है। आने वाला वर्ष भी मानवता को प्रकृति के कठोर रूप का सामना करा सकता है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन को केवल पर्यावरण मंत्रालयों या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का विषय मानना अब गंभीर भूल होगी। यह स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, जलस्रोत, आवास और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। जलवायु संकट की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसका सबसे बड़ा बोझ उन देशों और समुदायों पर पड़ रहा है, जिनका ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम रहा है। विकासशील और गरीब देशों के सामने एक साथ दो चुनौतियां हैं-विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना और जलवायु संकट से स्वयं को बचाना।

दशकों तक विकसित देशों ने औद्योगिक विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किया। आज जब विकासशील देश आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, उनसे उत्सर्जन कम करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए जलवायु न्याय का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वैश्विक समुदाय वास्तव में समाधान चाहता है तो विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, अनुकूलन और आपदा-रोधी ढांचे के लिए पर्याप्त वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देनी होगी। इसी संदर्भ में तुर्किये के अंताल्या में चल रहा सीओपी-31 महत्वपूर्ण है। सम्मेलन 9 से 20 नवंबर 2026 तक हो रहा है और इसका घोषित उद्देश्य जलवायु समाधानों के क्रियान्वयन तथा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को गति देना है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस बार दुनिया घोषणाओं से आगे बढ़कर वास्तविक कार्रवाई करेगी?

पिछले अनेक जलवायु सम्मेलनों में महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित हुए, लेकिन वास्तविक क्रियान्वयन की गति अपेक्षाकृत धीमी रही। आज आवश्यकता नए संकल्पों की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि पुराने संकल्पों को धरातल पर उतारने की है। विकसित देशों को वित्तीय दायित्वों को गंभीरता से लेना होगा। विकासशील देशों को तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाकर सौर, पवन, जल और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को तेजी से बढ़ाना होगा। शहरों की नियोजन व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, भवन निर्माण, कृषि और उद्योग-हर क्षेत्र को जलवायु अनुकूल बनाना होगा। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है या नहीं। सवाल यह है कि हम इसके सामने कितनी जल्दी और कितनी ईमानदारी से खड़े होते हैं।

भारत के संदर्भ में स्थिति और भी गंभीर है। देश एक ओर बढ़ती गर्मी, अनियमित मानसून, बाढ़ और सूखे का सामना कर रहा है, तो दूसरी ओर महानगरों में वायु प्रदूषण ने स्वास्थ्य संकट को गहरा कर दिया है। दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के आसपास प्रदूषण का जो भयावह स्तर देखने को मिला, उसने स्पष्ट कर दिया कि वायु केवल जीवन का आधार नहीं, बल्कि अब स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकट भी बन सकती है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई, खांसी और अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अस्पतालों और चिकित्सकों पर दबाव बढ़ता है। यह स्थिति केवल मौसमी परेशानी नहीं मानी जा सकती। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन एक-दूसरे से अलग संकट नहीं हैं। जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग दोनों समस्याओं को बढ़ाता है। इसलिए दिल्ली की जहरीली हवा और दुनिया के बढ़ते तापमान के बीच एक गहरा संबंध है।

कोविड-19 के दौरान भारत ने अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपातस्थिति का सामना किया था। उस समय प्रशासन, स्वास्थ्य तंत्र, नागरिक समाज और आम जनता ने मिलकर संकट का सामना किया। आज वायु प्रदूषण को लेकर भी वैसी ही गंभीरता की आवश्यकता है। इसका अर्थ केवल औपचारिक रूप से आपातकाल घोषित करना नहीं, बल्कि जन-स्वास्थ्य केंद्रित आपातकालीन कार्ययोजना तैयार करना है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के अत्यधिक स्तर पर स्कूलों, निर्माण गतिविधियों, यातायात, औद्योगिक उत्सर्जन, पराली और कचरा जलाने आदि को लेकर तत्काल और समन्वित कार्रवाई होनी चाहिए। अस्पतालों को तैयार रखना, संवेदनशील नागरिकों के लिए स्वास्थ्य परामर्श, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और प्रदूषण के स्रोतों पर वास्तविक नियंत्रण आवश्यक है। भारत सरकार को राज्यों के साथ मिलकर ऐसी स्थायी व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें प्रदूषण को केवल सर्दियों की समस्या न समझा जाए। वर्षभर वायु गुणवत्ता की निगरानी, उत्सर्जन नियंत्रण और स्वास्थ्य प्रभावों का वैज्ञानिक आकलन होना चाहिए।

भारत के पास दुनिया को केवल तकनीकी समाधान देने की ही नहीं, बल्कि जीवन-दृष्टि देने की भी क्षमता है। भारतीय संस्कृति ने सदियों पहले प्रकृति को उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का सहचर माना। जैन दर्शन का अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश आज जलवायु संकट के दौर में अत्यंत प्रासंगिक हो सकता है। आवश्यकता से अधिक उपभोग, अंधाधुंध संसाधन-दोहन और प्रकृति पर प्रभुत्व की मानसिकता को बदलना होगा। हमें विकास और पर्यावरण को परस्पर विरोधी मानने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। ऐसा विकास चाहिए जो रोजगार दे, अर्थव्यवस्था को गति दे, लेकिन हवा, पानी, मिट्टी और जंगलों को नष्ट न करे। यही वास्तविक सतत विकास है। आज सीओपी-31 से दुनिया को एक और घोषणापत्र की नहीं, दृढ़ इच्छाशक्ति, आर्थिक प्रतिबद्धता और समयबद्ध कार्रवाई की आवश्यकता है। जलवायु संकट की घड़ी में निष्क्रियता भी एक प्रकार का निर्णय है और उसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। धरती हमें चेतावनी दे रही है। तापमान बढ़ रहा है, समुद्र गर्म हो रहे हैं, बर्फ पिघल रही है और शहरों की हवा जहरीली हो रही है। अब भी समय है कि मानवता अपनी विकास-दृष्टि पर पुनर्विचार करे। प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, सह-अस्तित्व ही भविष्य का रास्ता है। यदि हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां यह सवाल जरूर पूछेंगी-जब खतरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, तब दुनिया ने कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों की?

प्रेरणा

विजय का असली रहस्य शस्त्रों में नहीं, चरित्र में छिपा होता है

मनुष्य की पहचान उसकी शक्ति, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और आचरण से होती है। इतिहास में ऐसे अनेक योद्धा हुए, जिन्होंने अपनी वीरता से बड़े-बड़े साम्राज्यों को जीत लिया, लेकिन अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय नहीं पा सके। इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी हुए, जिनके पास अपार सैन्य शक्ति नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने आदर्शों, मर्यादा और संस्कारों से पूरी दुनिया के हृदय पर राज किया। रामायण में भगवान श्रीराम और लंकापति रावण का चरित्र इसी अंतर को समझने का सबसे सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। रावण कोई साधारण राजा नहीं था। वह महान विद्वान, वेदों का ज्ञाता, भगवान शिव का परम भक्त और अद्भुत पराक्रमी योद्धा था। उसके पास सोने की लंका थी, विशाल सेना थी और संसार के बड़े-बड़े योद्धा उससे भय खाते थे। उसने अपनी तपस्या और सामर्थ्य से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। देवताओं तक को उसने चुनौती दी थी। कुबेर जैसे शक्तिशाली लोकपाल को पराजित कर उसकी पुष्पक विमान तक छीन लिया था। उसके ज्ञान, बल और वैभव की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। लेकिन इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद रावण अपने अहंकार और अनियंत्रित इच्छाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सका।

उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका चरित्र था। वह जानता था कि पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालना अधर्म है, लेकिन अपनी इच्छा और अहंकार के सामने उसने सारे ज्ञान और विवेक को भुला दिया। माता सीता का हरण करके उसने न केवल भगवान श्रीराम को चुनौती दी, बल्कि अपने ही विनाश का रास्ता खोल दिया। उसके पास शक्ति थी, बुद्धि थी और ज्ञान भी था, लेकिन इन सबको सही दिशा देने वाला संयम नहीं था।

रामायण से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग इस अंतर को बेहद सुंदर ढंग से समझाता है। कहा जाता है कि रावण के वध के बाद एक दिन उसकी पत्नी मंदोदरी भगवान श्रीराम से मिलने पहुंचीं। श्रीराम उस समय शांत भाव से बैठे हुए थे। जैसे ही मंदोदरी की छाया उनके पीछे पड़ी, वे तुरंत अपने स्थान से उठ खड़े हुए और अत्यंत सम्मान के साथ बोले, 'माता! आप यहां कैसे?'

श्रीराम के इस व्यवहार को देखकर मंदोदरी कुछ क्षण के लिए मौन रह गईं। उनके मन में एक प्रश्न था, जिसका उत्तर वह लंबे समय से तलाश रही थीं। उन्होंने श्रीराम से कहा, 'मैं यहां तुम्हें कोसने या अपने पति की मृत्यु का दुख सुनाने नहीं आई हूं। मैं तो केवल यह जानना चाहती हूं कि जिसने संसार के बड़े-बड़े योद्धाओं को पराजित किया, जिसने देवताओं तक को चुनौती दी, जिसके सामने बड़े-बड़े राजा सिर झुकाते थे, उस महापराक्रमी रावण को आखिर किसने हराया? तुममें ऐसी कौन-सी विशेषता थी, जो मेरे पति में नहीं थी?'

मंदोदरी का प्रश्न केवल एक पराजित पत्नी का प्रश्न नहीं था, बल्कि उस स्त्री की जिज्ञासा थी, जिसने अपने पति के पास अपार सामर्थ्य होने के बावजूद उसका पतन देखा था। वह समझना चाहती थीं कि आखिर युद्ध में हारने और जीवन में हारने के बीच क्या अंतर होता है।

भगवान श्रीराम ने विनम्रता से पूछा, 'माता! क्या आपको उस अंतर का पता चल गया है?' इस पर मंदोदरी ने उत्तर दिया, 'हां, अब मैं समझ गई हूं। एक मेरा पति था, जिसके पास मेरे जैसी पत्नी होने के बावजूद वह दूसरे की पत्नी को पाने की इच्छा रखता था। दूसरी ओर तुम हो, जिसके सामने एक पराई स्त्री की छाया मात्र पड़ते ही तुम सम्मानपूर्वक खड़े हो गए और उसे माता कहकर संबोधित किया। यही अंतर था तुम्हारे और रावण के चरित्र में।'

यह प्रसंग एक गहरी जीवन शिक्षा देता है। हालांकि यह कथा लोकप्रचलित प्रेरक प्रसंग के रूप में सुनाई जाती है, लेकिन इसका संदेश रामायण के मूल आदर्शों से जुड़ा हुआ है। भगवान श्रीराम का जीवन मर्यादा, सम्मान, संयम और कर्तव्य का प्रतीक है, जबकि रावण का पतन अहंकार, वासना और अनियंत्रित इच्छाओं का परिणाम था।

आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में सफलता का आकलन अक्सर धन, पद, प्रतिष्ठा, बड़े मकान, महंगी गाड़ियों और सामाजिक प्रभाव से किया जाता है। लोग दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन इस दौड़ में कई बार अपने संस्कार और नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य से करता है।

चरित्र की परीक्षा तब नहीं होती, जब कोई हमें देख रहा हो। असली परीक्षा तब होती है, जब हमारे पास गलत करने का अवसर हो, कोई रोकने वाला न हो और फिर भी हम अपने संस्कारों के कारण गलत रास्ते पर कदम न रखें। दूसरों की स्त्री को सम्मान देना, कमजोर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, अपने पद का दुरुपयोग न करना और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही वास्तविक महानता है।

रावण की हार केवल श्रीराम के बाणों से नहीं हुई थी। उसका पतन उस दिन शुरू हो गया था, जब उसने अपने विवेक की आवाज को अनसुना कर दिया था। दूसरी ओर श्रीराम की महानता केवल उनकी विजय में नहीं, बल्कि उन आदर्शों में थी, जिनका उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी पालन किया। इसलिए जीवन में बड़ा बनने से पहले अच्छा इंसान बनना आवश्यक है। धन और शक्ति से दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन सम्मान केवल चरित्र से प्राप्त होता है। तलवार से किसी राज्य को जीता जा सकता है, मगर लोगों के दिल जीतने के लिए मर्यादा और संस्कार चाहिए। अंततः मनुष्य की सबसे बड़ी विजय वही है, जब वह दूसरों पर शासन करने से पहले अपनी इच्छाओं, अहंकार और कमजोरियों पर शासन करना सीख लेता है। यही चरित्र की असली ताकत है।

चुनाव जीतने में माहिर BJP कार्यकर्ताओं को पद देने में फिसड्डी क्यों है? खाली पड़े पदों को भरने में सुस्ती क्यों दिखा रही है मोदी सरकार?

भारतीय जनता पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है। पार्टी के पास करोड़ों सदस्य हैं, देश के कोने-कोने में संगठन है और बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। चुनाव आते ही पार्टी के बड़े नेता रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में जुट जाते हैं। असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए बैठकों का दौर चलता है। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं को मनाने के लिए संगठन के बड़े पदाधिकारी मैदान में उतरते हैं। किसी को संगठन में जिम्मेदारी देने का भरोसा दिया जाता है तो किसी को भविष्य में राजनीतिक अवसर मिलने का आश्वासन।लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्र में भाजपा की अपनी सरकार है, सत्ता उसके हाथ में है और केंद्र सरकार के अधीन सैकड़ों आयोग, अकादमियां, बोर्ड और स्वायत्त संस्थाएं हैं, जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली पड़े हैं, तो फिर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने में इतनी बेरुखी क्यों?

दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) इसका एक उदाहरण है। इसके अध्यक्ष का पद लंबे समय से खाली है। परेश रावल का कार्यकाल 2024 में समाप्त हुआ था। इसके बावजूद अब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो पाई। NSD के उपाध्यक्ष का कार्यकाल जनवरी 2027 में समाप्त होगा, जबकि कई सदस्यों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2027 में खत्म होने वाला है। यानी समय रहते नियुक्तियां नहीं हुईं तो संस्थान में नेतृत्व और प्रतिनिधित्व का संकट और गहरा सकता है। इसी तरह संस्कृति मंत्रालय के अधीन ललित कला अकादमी में भी अध्यक्ष और जनरल काउंसिल के पदों को लेकर लंबे समय से रिक्तियों की स्थिति बनी हुई है। जनरल काउंसिल का कार्यकाल मई 2023 में समाप्त हो गया था और अध्यक्ष का कार्यकाल मार्च 2026 में पूरा हुआ।

यही नहीं, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) में उपाध्यक्ष का पद जुलाई 2019 से खाली है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों का प्रावधान है। इसके बावजूद पदों को भरने में मोदी सरकार की सुस्ती सवालों के घेरे में है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) में भी उपाध्यक्ष और सदस्य के पद लंबे समय तक खाली रहे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) में भी उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) में अध्यक्ष और छह सदस्यों के पद भी दो साल से ज्यादा समय से खाली पड़े हैं। यह तो महज कुछ उदाहरण हैं, जबकि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधीन आने वाले आयोगों, परिषदों, बोर्डों, अकादमियों और स्वायत्त संस्थाओं में रिक्त पदों की फेहरिस्त कहीं अधिक लंबी है। सवाल यह है कि आखिर कितने ऐसे पद हैं, जिन पर वर्षों से नियुक्तियां नहीं हुई हैं? कितने संस्थान बिना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के केवल प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं? यहां एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि जिस पार्टी की सरकार सत्ता में है, उस सरकार की नीतिगत और वैचारिक प्राथमिकताओं को संस्थानों में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? क्या यह काम नौकरशाही करेगी या फिर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से आने वाले वे लोग, जो सरकार की विचारधारा और दृष्टिकोण को समझते हैं? जब भाजपा के नेताओं के पास जिम्मेदारी और अवसर की आस लगाए बैठे कार्यकर्ताओं के बायोडाटा का अंबार लगा है, तो फिर नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? क्या पार्टी के पास योग्य कार्यकर्ताओं का अकाल पड़ गया है? क्या वर्षों तक संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं में से एक भी ऐसा नहीं है, जिसे किसी संस्थान की जिम्मेदारी सौंपी जा सके? या फिर सत्ता में आने के बाद पार्टी को अपने ही कार्यकर्ताओं की प्रतिभा और जरूरत याद नहीं रहती? चुनाव के वक्त कार्यकर्ताओं को मनाने और उन्हें जिम्मेदारी देने के वादे करने वाला संगठन आखिर सत्ता में रहते हुए इन खाली पदों को भरने के लिए सक्रिय क्यों नहीं दिखाई देता?

देखा जाये तो भाजपा की राजनीति में एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाई देता है। चुनाव से पहले जब किसी राज्य में असंतोष उभरता है, किसी नेता की नाराजगी सामने आती है या कार्यकर्ताओं में निराशा फैलती है तो संगठन के बड़े नेता तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। रूठों को मनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। नाराज नेताओं को फोन किए जाते हैं, बैठकें होती हैं और उन्हें जिम्मेदारी देने के वादे किए जाते हैं। लेकिन जब सत्ता हाथ में होती है, तब यही संगठन अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के मामले में सुस्त हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या कार्यकर्ताओं को मनाने का काम केवल चुनाव तक ही सीमित है? क्या चुनाव जीतने के बाद उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है? क्या पार्टी के लिए वर्षों तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं को केवल पोस्टर लगाने, रैलियों में भीड़ जुटाने और चुनाव प्रचार करने तक ही सीमित रखा जाएगा?

एक तरफ कार्यकर्ता अपना बायोडाटा लेकर पार्टी के संगठनात्मक पदाधिकारियों के चक्कर लगाते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें भी किसी आयोग, अकादमी या संस्थान में काम करने का अवसर मिले। वे अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर किसी संस्थान को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहते हैं।

अभियान

छठी मइया की महिमा अपरंपार, संतान सुख और रक्षा का देती हैं वरदान

भारतीय धार्मिक परंपराओं में छठ महापर्व का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। यह ऐसा लोकपर्व है, जिसमें प्रकृति के प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना के साथ मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और विश्वास भी प्रकट किया जाता है। चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत में श्रद्धालु पूरी निष्ठा, पवित्रता और अनुशासन के साथ पूजा-अर्चना करते हैं। इस दौरान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने के साथ छठी मइया की विशेष आराधना की जाती है। मान्यता है कि छठी मइया बच्चों को संकटों से बचाती हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करती हैं तथा परिवार में सुख-समृद्धि बनाए रखती हैं। यही कारण है कि संतान की मंगलकामना करने वाली माताएं इस महापर्व को अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाती हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मइया को षष्ठी देवी का स्वरूप माना जाता है। उनका उल्लेख पुराणों और लोकपरंपराओं में बालकों की रक्षक देवी के रूप में मिलता है। उन्हें संतान प्रदान करने वाली, बच्चों का पालन-पोषण करने वाली और उनके जीवन की बाधाओं को दूर करने वाली मातृशक्ति माना गया है। कुछ लोकमान्यताओं में छठी मइया को सूर्य देव की बहन भी कहा जाता है। इसी विश्वास के चलते छठ पर्व में सूर्य उपासना और षष्ठी देवी की आराधना एक साथ की जाती है। हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों में उनकी उत्पत्ति और स्वरूप को लेकर अलग-अलग कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सभी मान्यताओं का मूल भाव संतान की रक्षा और परिवार का कल्याण ही है।

षष्ठी देवी के स्वरूप को समझने के लिए राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की पौराणिक कथा विशेष रूप से सुनाई जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत एक प्रतापी और धर्मपरायण शासक थे। उनके राज्य में धन-धान्य, वैभव और सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी रानी मालिनी भी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा अभाव था, जो तमाम सुखों के बावजूद उन्हें भीतर से दुखी रखता था। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में दोनों का जीवन व्यतीत हो रहा था।

संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर राजा ने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः उन्होंने महर्षि कश्यप से मार्गदर्शन मांगा। महर्षि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा ने ऋषि के निर्देशानुसार पूरे विधि-विधान से यज्ञ का आयोजन कराया। यज्ञ संपन्न होने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हुईं। लंबे इंतजार के बाद जब उनके घर पुत्र का जन्म हुआ तो राजमहल में खुशियां छा गईं। लेकिन यह खुशी अधिक समय तक नहीं टिक सकी, क्योंकि जन्म लेने वाला बालक मृत था।

यह समाचार सुनते ही राजा और रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिली संतान को इस अवस्था में देखकर राजा प्रियव्रत अत्यंत व्याकुल हो गए। वे अपने भाग्य को कोसने लगे। पुत्र वियोग में उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने जीवन समाप्त करने का निर्णय कर लिया। उसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसके बीच एक तेजस्वी देवी दिखाई दीं। उन्होंने राजा को बताया कि वे षष्ठी देवी हैं और संसार के बच्चों की रक्षा करने वाली शक्ति हैं।

देवी ने राजा को समझाया कि जीवन में निराशा के सामने हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने राजा को अपनी आराधना करने का विधान बताया और संतान सुख का आशीर्वाद दिया। राजा प्रियव्रत ने पूरी श्रद्धा से देवी की पूजा की। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद षष्ठी देवी की पूजा की परंपरा का विस्तार हुआ। तभी से उन्हें बच्चों की रक्षा करने वाली और परिवार को संतान का सुख देने वाली देवी के रूप में पूजा जाने लगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा में बच्चे के जन्म के छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा का विधान भी मिलता है। लोकविश्वास है कि इस दिन देवी नवजात शिशु के जीवन और भविष्य की रक्षा करती हैं। परिवार के लोग बच्चे के स्वस्थ जीवन, अच्छे भाग्य और लंबी आयु की कामना करते हैं। कई स्थानों पर इस अवसर पर विशेष पूजा, कथा और पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं। यही मान्यता छठी मइया के प्रति लोगों की श्रद्धा को और गहरा बनाती है।

छठ महापर्व में छठी मइया की पूजा का उद्देश्य केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है। इस आराधना में बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, दीर्घायु और उज्ज्वल भविष्य की कामना भी शामिल होती है। माताएं चाहती हैं कि उनकी संतान जीवन में आने वाली कठिनाइयों से सुरक्षित रहे और उसे सफलता तथा सम्मान प्राप्त ह

कतर, ओमान और यूएई में वाइब्रेंट गुजरात 2027 के लिए गुजरात सरकार का मिशन सफलतापूर्वक संपन्न; प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनी

गुजरात सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सप्ताहभर चली इस यात्रा के दौरान तीनों देशों के सॉवरेन वेल्थ फंड, निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और ऊर्जा कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित कीं

गांधीनगर : वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (वीजीजीएस) बिजनेस, निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत का एक अग्रणी प्लेटफॉर्म है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 11वाँ संस्करण आगामी 10 से 12 जनवरी, 2027 के दौरान गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित होगा।

गुजरात सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 25 से 31 अक्टूबर, 2026 के दौरान कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस मिशन से खाड़ी देशों के साथ राज्य की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है तथा आगामी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (वीजीजीएस) 2027 की तैयारियों को और गति मिली है। इस यात्रा के दौरान वैश्विक निवेश, व्यापार, नवाचार (इनोवेशन), मैन्युफैक्चरिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में गुजरात में उपलब्ध अवसरों का प्रदर्शन किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गुजरात सरकार के श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री लोचन सेहरा ने किया। इसमें गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रीय एजेंसियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल थे। एक सप्ताह की इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने तीनों देशों के सॉवरेन वेल्थ फंड, निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों, ऊर्जा कंपनियों, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों, इंडस्ट्रियल डेवलपर्स, शैक्षणिक संस्थानों और गुजराती बिजनेस समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद किया।



इस मिशन में फाइनांस, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह (पोर्ट्स), इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, शिक्षा, शहरी विकास, रिटेल और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप गुजरात में संभावित निवेश एवं सहयोग के मजबूत अवसर सृजित हुए हैं।

मिशन के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने 25 से अधिक वन-टू-वन बैठकें, कई सेक्टर आधारित राउंडटेबल संवाद, साइट विजिट और डायस्पोरा (प्रवासी भारतीय) कार्यक्रम आयोजित किए। बिजनेस राउंडटेबल में 160 से अधिक संस्थागत प्रतिनिधि जुड़े, जबकि नेटवर्किंग तथा निवेश से जुड़े कार्यक्रमों में गुजराती डायस्पोरा और बिजनेस समुदाय के 500 से अधिक सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस यात्रा के दौरान कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (क्यूआईए), कतर फाइनेंशियल सेंटर (क्यूएफसी), कतर एनर्जी, कतर नेशनल बैंक, कतर डेवलपमेंट बैंक, ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ओआईए), ओमान एलएनजी, क्यूक्यू, अस्याद ग्रुप, पोर्ट ऑफ दुक्म, पोर्ट ऑफ सोहार, लिमाड होल्डिंग्स, केजाद ग्रुप, एडनॉक, डीएमसीसी, एमार ग्रुप, नेस्टो, रैक बैंक और ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप जैसी अग्रणी संस्थाओं के साथ प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित हुईं।

इस मिशन का मुख्य आकर्षण तीनों देशों के सॉवरेन वेल्थ फंड और रणनीतिक निवेश संस्थाओं (जैसे कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और लिमाड होल्डिंग्स) के साथ हुई बैठकें रहीं, जिनमें उनके साथ सीधा संवाद किया गया। इन चर्चाओं में राज्य की दीर्घकालीन विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप गुजरात में निवेश के अवसरों को लेकर काफी रुचि दिखाई गई। प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के निवेशोन्मुखी इकोसिस्टम का विस्तृत प्रदर्शन किया, जिसमें विशेष रूप से गिफ्ट सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय सेवाओं, इनोवेशन और उभरती टेक्नोलॉजी पर बल दिया गया। अग्रणी वित्तीय संस्थानों और निवेश संस्थाओं के साथ बातचीत में गिफ्ट सिटी में बैंकिंग, बीमा (इंश्योरेंस), ट्रेजरी, फंड मैनेजमेंट और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने के अवसरों पर फोकस किया गया। कई संस्थाओं ने गुजरात के पॉलिसी फ्रेमवर्क, टैलेंट पूल और बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाकर राज्य से अपने क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालन का विस्तार करने में रुचि दर्शाई।

कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ चर्चा में रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर, हेल्थकेयर, बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, वेंचर कैपिटल और स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य उच्च विकास वाले क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

इस यात्रा के कार्यक्रम में ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधारस्तंभ के रूप में उभरा। प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा सुरक्षा, एलएनजी, रणनीतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश और भविष्य के ऊर्जा समाधानों में दीर्घकालीन साझेदारी को मजबूत करने के विषय में कतर एनर्जी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी), क्यूक्यू, ओमान एलएनजी और ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा; हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, रीगैसिफिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर और संबंधित एनर्जी वैल्यू चेन में उपलब्ध अवसरों की भी पड़ताल की गई। इसके अतिरिक्त; एडीएनओसी की निवेश शाखा 'एक्सआरजी' ने भारत में रणनीतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेशों का मूल्यांकन करने में रुचि दिखाई।

ओमान और यूएई की यात्राओं ने लॉजिस्टिक्स, बंदरगाहों और औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय गति पैदा की है। अस्याद ग्रुप, पोर्ट ऑफ दुक्म और पोर्ट ऑफ सोहार के साथ चर्चा में गुजरात और ओमान के बीच व्यापार कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स दक्षता और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए 'गुजरात-ओमान इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर' के संभावित विकास पर विचार किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट मॉडल का अध्ययन करने और सहयोग के संभावित रास्तों की पहचान करने के लिए ओमान में 'खजाएन इकोनॉमिक सिटी' का भी दौरा किया। यूएई में, खलीफा इकोनॉमिक ज़ोन्स अबू धाबी (केईजेडएडी) ग्रुप, ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप और नेस्टो के साथ बैठकों में इंडस्ट्रियल पार्क, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, वेयरहाउसिंग, कोल्ड-चेन सुविधाओं, रिटेल विस्तार और सप्लाई-चेन विकास के अवसरों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

इस मिशन ने शहरी विकास क्षेत्र में सहयोग के नए द्वार भी खोले हैं। एमार ग्रुप के साथ चर्चा में गुजरात में इंटीग्रेटेड टाउनशिप, कॉमर्शियल रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और भविष्य के लिए तैयार शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अवसरों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने ओमान की अग्रणी संस्थाओं के साथ शैक्षणिक एवं कौशल (स्किलिंग) सहयोग के अवसरों की भी पड़ताल की, जिसमें गुजरात की कौशल्य – द स्किल यूनिवर्सिटी से जुड़ी साझेदारी शामिल है। ये चर्चाएँ शैक्षणिक आदान-प्रदान, ऑनलाइन लर्निंग, फैकल्टी सहयोग और वर्कफोर्स डेवलपमेंट की पहलों पर केन्द्रित रहीं।

इस कार्यक्रम की एक बड़ी विशेषता यह रही कि तीनों देशों में रहने वाले गुजराती समुदाय (डायस्पोरा) की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली।

15 दिसंबर को अहमदाबाद मंडल पर पेंशन अदालत का आयोजन



पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबन्धित प्रश्नों के त्वरित निपटारे के लिए 15 दिसंबर, 2026 (मंगलवार) को पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी श्री सिद्धार्थ के अनुसार अहमदाबाद मण्डल से जो भी कर्मचारी सेवानिवृत हुए है उन पेंशनर/फेमिली पेंशनर के पेंशन संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अहमदाबाद में दिनांक 15.12.2026 (मंगलवार) को पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

अहमदाबाद मंडल से जो भी कर्मचारी रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं वह पेंशनर/फैमिली पेंशनर अपनी पेंशन संबंधित शिकायतें है वह अपना आवेदन (तीन प्रतियों में) दिनांक 17.11.2026 तक मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय (स्थापना), अहमदाबाद मण्डल पश्चिम रेलवे, GCS हॉस्पिटल के सामने अमदुपुरा अहमदाबाद को भेज सकते हैं। आवेदन में अपना नाम, पदनाम, अंतिम वेतन, भर्ती तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि PPO प्रति एवं शिकायत का प्रकार अवश्य दर्ज करें। यदि कोई पेंशनर Email द्वारा आवेदन करना चाहे तो वह नीचे दी गई Email-ID पर आवेदन कर सकते है। Email ID- pensionadalat2020adi@gmail.com

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में जनजातीय गौरव दिवस आयोजित



भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे छठे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज पश्चिम रेलवे वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुंडा के अदम्य साहस, संघर्ष, त्याग तथा जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए किए गए उनके ऐतिहासिक योगदान का स्मरण किया।

उत्राण - लालकुआँ के बीच वन वे स्पेशल ट्रेन सेवा



यात्रियों की सुविधा व मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे वडोदरा मंडल के उत्राण से लालकुआँ स्टेशन के बीच विशेष किराए पर स्पेशल ट्रेन की एक ट्रिप चलायी जा रही है।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेन नंबर 09121 उत्राण – लालकुआँ वन- वे स्पेशल उत्राण से 14 नवंबर 2026 को दोपहर 14:15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 13:20 बजे लालकुआँ पहुंचेगी।

यह ट्रेन भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम जंक्शन, कोटा जंक्शन, सवाई माधोपुर,भरतपुर जंक्शन, मथुरा जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन , गाजियाबाद, हापुर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर स्टेशनों पर ठहरेंगी।

इस ट्रेन में स्लीपर व द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे।

ट्रेन संख्या 09121 की बुकिंग 13 .11. 2026 शाम 19:00 बजे सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

15 नवंबर को अहमदाबाद और मधुबनी के बीच चलेगी वन-वे स्पेशल ट्रेन



पश्चिम रेलवे द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए अहमदाबाद और मधुबनी के बीच विशेष किराये पर वन-वे स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09431 अहमदाबाद–मधुबनी वन-वे स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 09431 अहमदाबाद–मधुबनी वन-वे स्पेशल ट्रेन 15 नवंबर 2026 (रविवार) को अहमदाबाद से प्रातः 10:10 बजे प्रस्थान करेगी तथा मंगलवार को रात्री 01:40 बजे मधुबनी पहुंचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन आणंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, उज्जैन, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, बीना, दमोह, कटनी मुड़वारा, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा एवं सकरी स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर श्रेणी तथा सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09431 के टिकटों की बुकिंग 14 नवंबर 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेन के ठहराव, समय एवं कोचों की संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस का भावनगर मंडल में उत्साहपूर्वक आयोजन



भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के पावन अवसर पर पूरे देश में 01 नवम्बर से 15 नवम्बर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में भावनगर मंडल में दिनांक 13 नवम्बर 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं जननायक भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती "जनजातीय गौरव दिवस" के रूप में बड़े हर्षोल्लास, उत्साह एवं श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मंडल सभागार में "जनजातीय गौरव सप्ताह" अंतर्गत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात उनके जीवन, संघर्ष एवं स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान पर आधारित प्रेरक वृत्तचित्र प्रदर्शित किया गया।

अपने संबोधन में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने न केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष कर आदिवासी समाज को एकजुट किया, बल्कि समाज सुधार एवं राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए भी विशिष्ट योगदान दिया। उनका सम्पूर्ण जीवन संघर्ष, आत्मसम्मान और देशभक्ति का प्रेरक प्रतीक है, जिससे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी।

सेमिनार के दौरान वक्ताओं द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान तथा आदिवासी समाज के उत्थान हेतु किए गए उनके कार्यों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारियों को उनके जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायी शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में शाखा अधिकारीगण, कर्मचारीगण, ट्रेड यूनियन एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन एवं संचालन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन के द्वारा किया गया।

जीएसआरटीसी की डिजिटल टिकटिंग क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि; एक ही दिन में सर्वाधिक 1,46,875 सीटों की बुकिंग

केवल मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ही 99,402 सीटों की बुकिंग

गांधीनगर : गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) ने डिजिटल टिकटिंग क्षेत्र में एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जीएसआरटीसी द्वारा ऑनलाइन पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम द्वारा देश के सभी राज्य परिवहन निगमों में एक ही दिन में सर्वाधिक बुकिंग तथा आय प्राप्त करने का नया इतिहास रचा गया है। इसके साथ ही जीएसआरटीसी ने लगातार 7वें वर्ष इस गौरवपूर्ण स्थान को बनाए रखते हुए समग्र देश में डंका बजाया है।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि के अंतर्गत 11 नवंबर को भाई दूज को एक ही दिन में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए। इस दिन राज्य में एक ही दिन में सर्वाधिक 1,46,875 सीटों की बुकिंग हुई, जो अब तक का सर्वोच्च आँकड़ा है। इसके अलावा; केवल मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा ही 99,402 सीटों की बुकिंग दर्ज की गई, जो यात्रियों में डिजिटल माध्यमों के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। डिजिटल बुकिंग के साथ-साथ आय के मामले में भी जीएसआरटीसी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस एक ही दिन में निगम को कुल 3.55 करोड़ रुपए की डिजिटल आय हुई है। इस आय में से केवल मोबाइल एप्लिकेशन से ही 2.27 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। यह पहल डिजिटल इंडिया के सपने को अधिक मजबूत बनाती है, जबकि एक ही दिन की कुल आय 13 करोड़ रुपए से अधिक हुई है।

जीएसआरटीसी के इस शानदार प्रदर्शन का इतिहास देखें, तो वर्ष 2019 में 74,368 सीटों और 1,53,10,717 रुपए की आय से शुरू हुई यह यात्रा क्रमशः आगे बढ़ते हुए वर्ष 2026 में सर्वोच्च शिखर पर पहुँची है। पिछले वर्षों के आँकड़ों पर नजर डालें, तो वर्ष 2022 में 1,14,880 सीटें की बुकिंग व 2.10 करोड़ रुपए आय, वर्ष 2023 में 1,32,177 सीटों व 2.97 करोड़ रुपए, वर्ष 2024 में 1,41,468 सीटों व 3.15 करोड़ रुपए और वर्ष 2025 में 1,33,043 सीटों की बुकिंग व 3.19 करोड़ रुपए की आय हुई थी। इस वर्ष इन सभी आँकड़ों को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है।

राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित करने पर निगम के सभी एसटी ड्राइवर, कंडक्टर तथा मैकेनिक सहित समस्त स्टाफ को हार्दिक अभिनंदन दिया है। त्योहारों के इस अवसर पर अपने परिवार की चिंता किए बिना यात्रियों को सुरक्षित और समय पर उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी निभाने पर उन्होंने सभी कर्मचारियों का विशेष आभार भी व्यक्त किया है।

देशभर के सभी राज्य परिवहन निगमों में डिजिटल बुकिंग में 'नंबर 1 एसटीयू' बनने का यह गौरव गुजरात राज्य को मिला है। यात्रियों को अत्याधुनिक, सरल और पारदर्शी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए जीएसआरटीसी प्रतिबद्ध है और इस उपलब्धि के लिए निगम ने यात्रियों का आभार व्यक्त किया है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने महुडी में किए श्री घंटाकर्ण महावीर के दर्शन; गुजरात की सुख-शांति और समृद्धि के लिए की प्रार्थना



गांधीनगर : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार को गांधीनगर जिले में स्थित जैन धर्म के अत्यंत पवित्र यात्राधाम महुडी में उपस्थित रहकर श्री घंटाकर्ण महावीर प्रभु के दर्शन किए और धन्यता की अनुभूति की।

श्री संघवी ने महुडी में आए दर्शनार्थियों तथा नगरजनों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि इस पवित्र स्थल पर श्री घंटाकर्ण स्वामी के दर्शन का लाभ मिलने से मन को अत्यंत अलौकिक आनंद हुआ है।

उन्होंने प्रार्थना की कि गुजरात की सुख, शांति और समृद्धि में निरंतर वृद्धि हो तथा राज्य के नागरिकों का जीवन सुखमय बने। इस अवसर पर माणसा के विधायक श्री जे. एस. पटेल तथा अन्य महानुभाव भी दर्शनार्थ उपस्थित रहे।

वडनगर रेलवे स्टेशन बना विरासत और आधुनिक रेल कनेक्टिविटी का प्रतीक, अंबाजी तक रेल पहुंचाने की दिशा में तेजी से कार्य,स्वदेशी मेला-2026 के दौरान वडनगर रेलवे स्टेशन से लगभग 6,000 यात्रियों ने की रेल यात्रा; वडनगर–वरेठा रेलखंड से क्षेत्रीय पर्यटन एवं आर्थिक विकास को मिल रही गति

अहमदाबाद, गुजरात का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर वडनगर आज अपनी समृद्ध विरासत के साथ आधुनिक रेल कनेक्टिविटी के नए आयाम स्थापित कर रहा है। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा वडनगर रेलवे स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित करने के साथ-साथ क्षेत्र के पर्यटन, व्यापार एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के लिए रेल कनेक्टिविटी को निरंतर मजबूत किया जा रहा है।

हाल ही में 30 अक्टूबर से 8 नवंबर 2026 तक वडनगर में आयोजित स्वदेशी मेला-2026 के दौरान लगभग 6,000 यात्रियों ने वडनगर रेलवे स्टेशन से रेल यात्रा की। इस दौरान स्टेशन से यात्रियों की आवाजाही ने स्थानीय स्तर पर आयोजित मेलों, सांस्कृतिक गतिविधियों, हस्तशिल्प, हथकरघा एवं ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने में रेल परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया। ऐसे आयोजनों के माध्यम से वडनगर को देश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने में रेलवे की उपयोगिता और अधिक स्पष्ट हुई है।

वडनगर–वरेठा रेलखंडः विकास और कनेक्टिविटी की मजबूत आधारशिला

महेसाणा–वरेठा ब्रॉडगेज रेल लाइन के अंतर्गत विकसित वडनगर रेलवे स्टेशन



क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण केंद्र है। वर्ष 2021 में महेसाणा–वरेठा के 55 किलोमीटर लंबे रेलखंड का आमान परिवर्तन 293.14 करोड़ की लागत से तथा विद्युतीकरण का कार्य 74.66 करोड़ की लागत से पूरा किया गया। इस प्रकार इस रेल परियोजना पर कुल 367.80 करोड़ खर्च किए गए।

इस रेलखंड पर कुल 10 स्टेशन हैं। इनमें वडनगर, विसनगर, खेरालु एवं वरेठा में नए स्टेशन भवन विकसित किए गए हैं। इस रेल कनेक्टिविटी से वडनगर को महेसाणा के माध्यम से अहमदाबाद–दिल्ली ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है।

वर्तमान में वडनगर से तीन जोड़ी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें वरेठा–गांधीनगर कैपिटल मेमू (69208/69207), वडनगर–वलसाड सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20960/20959) तथा वडनगर–बांद्रा टर्मिनस लोकशक्ति एक्सप्रेस (19018/19017) शामिल हैं।

विरासत की झलक के साथ आधुनिक यात्री सुविधाएं

वडनगर रेलवे स्टेशन की वास्तुकला को शहर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप विकसित किया गया है। स्टेशन भवन में पत्थर की आकर्षक नक्काशी, विशेष प्रवेश एवं निकास द्वार तथा सुव्यवस्थित लैंडस्केपिंग की गई है, जो वडनगर की समृद्ध विरासत को प्रतिबिंबित करती है।

यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर 425 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, कैफे सहित वेटिंग रूम, सामान्य एवं महिला यात्रियों के लिए अलग प्रतीक्षालय, शौचालय, पेयजल सुविधा तथा प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर 529.20 वर्ग मीटर का प्लेटफॉर्म कवर शेड उपलब्ध है। दिव्यांग यात्रियों के लिए रैंप, शौचालय एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

वडनगर–मोढेरा–पाटन हेरिटेज सर्किट से रेल कनेक्टिविटी का जुड़ाव इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है।

तारंगाहिल–अंबाजी–आबू रोड तक रेल कनेक्टिविटी का विस्तार

वडनगर और आसपास के क्षेत्रों के विकास को नई गति देने की दिशा में तारंगाहिल–अंबाजी–आबू रोड नई रेल लाइन परियोजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अतिरिक्त, वरेठा से अंबाजी तक प्रस्तावित रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से इस क्षेत्र को भविष्य में व्यापक रेल नेटवर्क से जोड़ने की संभावनाएं और मजबूत होंगी।

तारंगाहिल–अंबाजी–आबू रोड नई रेल लाइन लगभग 117 किलोमीटर लंबी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे वर्ष 2022-23 में लगभग 3,000 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ मंजूरी दी गई थी। परियोजना की अंतिम संशोधित कुल लागत लगभग 3,050 करोड़ है। इस परियोजना का उद्देश्य गुजरात और राजस्थान के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को रेल नेटवर्क से जोड़ना तथा क्षेत्र के निवासियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।

इस रेल लाइन के माध्यम से अंबाजी स्थित शक्तिपीठ, तारंगाहिल के जैन तीर्थस्थल, माउंट आबू तथा दिलवाड़ा जैन मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। यह परियोजना अहमदाबाद–आबू रोड रेल मार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने के साथ-साथ क्षेत्रीय परिवहन एवं माल ढुलाई को भी मजबूती प्रदान करेगी।

परियोजना के अंतर्गत 15 स्टेशन बनाए जा रहे है, जिनमें 8 क्रॉसिंग स्टेशन एवं 7 हॉल्ट स्टेशन शामिल हैं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाली इस रेल लाइन पर 11 सुरंगों, 54 बड़े पुलों, 151 छोटे पुलों, 8 रोड ओवर ब्रिज तथा 54 रोड अंडर ब्रिज/सीमित ऊंचाई के पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। यह विद्युतीकृत रेल मार्ग होगा।

परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जा चुका है। निर्माण कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ठेके आवंटित किए जा चुके हैं तथा विभिन्न निर्माण गतिविधियां तेजी से प्रगति पर हैं। निर्धारित समय-सीमा में परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित कार्यों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

पर्यटन, रोजगार और आर्थिक विकास को मिलेगा नया आयाम

वडनगर से लेकर अंबाजी और आगे राजस्थान के आबू रोड तक बेहतर रेल कनेक्टिविटी विकसित होने से उत्तर गुजरात के पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को व्यापक पहचान मिलने की उम्मीद है। इससे श्रद्धालुओं, पर्यटकों, स्थानीय व्यापारियों, किसानों एवं क्षेत्र के निवासियों को लाभ मिलेगा। साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प, लघु उद्योगों, कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण उद्यमिता को भी नए बाजार उपलब्ध होंगे।

वडनगर रेलवे स्टेशन आज ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक रेल सुविधाओं के संगम का प्रतीक बनकर उभर रहा है। वहीं, भविष्य की रेल परियोजनाएं इस क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर पर्यटन, व्यापार, रोजगार और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के नए अवसर सृजित करेंगी।

एकतरफा प्यार में हैवानियत की हदें पार, प्रस्ताव ठुकराने पर छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म

रांची। एकतरफा प्यार जब जुनून और बदले की भावना में बदल जाता है, तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं, इसका एक शर्मनाक मामला झारखंड की राजधानी रांची में सामने आया है। यहां एक नाबालिग ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर 18 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी नाबालिग छात्रा को पसंद करता था और कई बार उसके सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रख चुका था, लेकिन छात्रा ने हर बार उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसी बात से नाराज होकर उसने बदला लेने की योजना बनाई और अपने दो साथियों को भी इसमें शामिल कर लिया। आरोपियों ने पहले छात्रा की गतिविधियों पर नजर रखी, उसके आने-जाने का समय पता किया और फिर मौका देखकर उसे सुनसान स्थान पर घेर लिया। घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना सात नवंबर की शाम रांची के रातू थाना क्षेत्र के चटकपुर इलाके में हुई। 18 वर्षीय छात्रा रोज की तरह ट्यूशन पढ़ने गई थी। शाम को पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने घर लौट रही थी। रास्ते में एक ऐसा स्थान पड़ा, जहां आमतौर पर लोगों की आवाजाही कम रहती है। इसी सुनसान रास्ते पर पहले से घात लगाए बैठे तीन युवकों ने उसे रोक लिया। छात्रा कुछ समझ पाती, इससे पहले ही आरोपियों ने उसे जबरन अपने साथ खींच लिया और एक बाउंड्री के पीछे झाड़ियों की ओर ले गए। वहां तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब आरोपियों का विरोध किया और खुद को बचाने की कोशिश की, तो उसके साथ मारपीट भी की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह आहत थी। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद आठ नवंबर को रातू थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश



दिए। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई। टीम को आरोपियों की पहचान करने और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

जांच टीम ने सबसे पहले घटनास्थल और उसके आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि घटना के समय उस रास्ते से कौन-कौन गुजरा था और आसपास किन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके बाद घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की फुटेज जुटाई गई। पुलिस ने अलग-अलग कैमरों में कैद तस्वीरों और वीडियो का बारीकी से विश्लेषण किया। जांच के दौरान एक युवक छात्रा का पीछा करता हुआ दिखाई दिया। फुटेज में उसकी गतिविधियां पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सुराग साबित हुईं। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर युवक की पहचान करने की कोशिश शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि फुटेज में दिखाई देने वाला युवक नाबालिग है।

पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले की कई महत्वपूर्ण कड़ियां सामने आईं। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में नाबालिग ने स्वीकार किया कि वह छात्रा से एकतरफा प्यार करता था। वह छात्रा के सामने कई बार अपने प्यार का प्रस्ताव रख चुका था, लेकिन छात्रा ने उसकी बात स्वीकार नहीं की। हर बार प्रस्ताव ठुकराए जाने से वह नाराज रहने लगा था। धीरे-धीरे उसकी नाराजगी बदले की भावना में बदल गई। पुलिस का कहना है कि इसी मानसिकता के चलते उसने छात्रा को सबक सिखाने के नाम पर अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर इस जघन्य वारदात की योजना बनाई।

जांच में यह भी सामने आया कि वारदात अचानक नहीं हुई थी, बल्कि आरोपियों ने पहले से इसकी तैयारी की थी। तीनों ने छात्रा की दिनचर्या पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। वे यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि छात्रा किस समय ट्यूशन जाती है, पढ़ाई के बाद कितने बजे घर लौटती है और रास्ते में उसके साथ कोई रहता है या नहीं। उन्होंने उसके आने-जाने के रास्ते और उन स्थानों की जानकारी जुटाई, जहां लोगों की आवाजाही कम रहती है। पुलिस के मुताबिक, कई दिनों तक रेकी करने के बाद आरोपियों ने सात नवंबर की शाम को वारदात को अंजाम देने का फैसला किया। उन्हें जानकारी थी कि उस समय छात्रा ट्यूशन से अकेले घर लौटती है। इसी का फायदा उठाकर तीनों ने उसे रास्ते में रोक लिया।

पुलिस के अनुसार, नाबालिग से पूछताछ के दौरान उसके दोनों साथियों के बारे में भी जानकारी मिली। इसके बाद जांच टीम ने उनकी पहचान और संभावित ठिकानों का पता लगाने के लिए तकनीकी साक्ष्यों तथा अन्य उपलब्ध जानकारियों का सहारा लिया। पुलिस ने दोनों संदिग्धों की गतिविधियों की जांच की और मामले में उनकी संलिप्तता से जुड़े साक्ष्य जुटाए। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंकज लोहरा और अंशु राणा के रूप में हुई है। पंकज लोहरा लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है, जबकि अंशु राणा चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र से संबंधित है। पुलिस दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजने की तैयारी कर रही है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक गौरव गोस्वामी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की। नाबालिग से पूछताछ में उसके दोनों साथियों की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल नाबालिग को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्यूशन से घर लौट रही एक छात्रा को रास्ते में घेरकर इस तरह की वारदात को अंजाम देना बताता है कि अपराधियों ने न केवल उसकी सुरक्षा को निशाना बनाया, बल्कि उसकी स्वतंत्रता और सामान्य जीवन को भी गहरी चोट पहुंचाई। किसी व्यक्ति के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करना या अस्वीकार करना पूरी तरह उसका निजी अधिकार है। किसी की असहमति को अपमान समझकर बदला लेने की कोशिश करना अपराध है और इसके लिए किसी भी तरह का बहाना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

विशेषज्ञों का मानना है कि एकतरफा आकर्षण को प्रेम समझना और सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध उस पर दबाव बनाना गंभीर सामाजिक समस्या है। किसी के इनकार को स्वीकार न कर पाना, पीछा करना, धमकी देना या बदले की भावना पालना ऐसे व्यवहार हैं, जिन्हें समय रहते गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस तरह की घटनाएं केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं हैं, बल्कि समाज में सहमति, सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को भी सामने लाती हैं।

फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के बाद मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। अब जांच एजेंसियों के सामने घटना से जुड़े सभी साक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से जुटाने और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पीड़िता को उचित सुरक्षा, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि वह इस भयावह अनुभव से उबरकर सामान्य जीवन की ओर लौट सके। रांची की यह घटना समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्रेम के नाम पर किसी की इच्छा, सम्मान और सुरक्षा को कुचलने की मानसिकता के खिलाफ परिवार, समाज और कानून—तीनों स्तरों पर सख्त रुख अपनाना कितना जरूरी है।

गुजरात के शहर स्वच्छता के क्षेत्र में देश में अग्रणी : दिल्ली में राष्ट्रपति के करकमलों से स्वच्छ शहरों को पुरस्कार प्रदान किए गए

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात में स्वच्छता लोगों की जीवनशैली बनी है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर : भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत शहरी विकास विभाग द्वारा गुजरात के शहरों को स्वच्छता के क्षेत्र में देशभर में अग्रणी रहने के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के करकमलों से नई दिल्ली में ये पुरस्कार अहमदाबाद-साणंद, वडोदरा और सूरत के शहरी प्रशासन को प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी रहने के लिए इन शहरों एवं नागरिकों को हार्दिक बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में स्वच्छता के लिए जो जन आंदोलन चलाया है, उसे गुजरात ने भली-भाँति साकार किया है।

प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन में स्वच्छता राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की जीवनशैली बन गई है, मुख्यमंत्री ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी से स्वच्छ एवं विकसित गुजरात की दिशा में और अधिक तेज गति से आगे बढ़ने



का आह्वान किया है।

राज्य के जिन शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्थान मिला है, उनमें स्वच्छ शहरों की जोड़ी श्रेणी में अहमदाबाद-साणंद को मेंटर और मेंटी सिटी के रूप में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

शहरी कचरा प्रबंधन में उत्कृष्टता को वेग देने के लिए इस स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छता लीग श्रेणी में सूरत ने लगातार दूसरी बार देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

इतना ही नहीं; वडोदरा महानगर को राज्य के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

नई दिल्ली में आयोजित इस पुरस्कार वितरण समारोह में शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई, राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला और संबंधित महानगर पालिकाओं के अधिकारियों ने ये पुरस्कार स्वीकार किए।

पत्नी को ब्रिटेन में पढ़ाने का सपना पड़ा भारी, कर्ज के दबाव में लूटा 37 लाख का सोना-हीरा

जयपुर। विदेश में पढ़ाई करने और पत्नी को ब्रिटेन (यूके) में उच्च शिक्षा दिलाने का सपना एक युवक को अपराध के रास्ते पर ले गया। कर्ज की किस्तें चुकाने और आर्थिक परेशानियों से निकलने के बजाय उसने जयपुर के एक प्रतिष्ठित ज्वैलरी शोरूम को निशाना बनाकर करीब 37 लाख रुपये के आभूषण लूट लिए। वैशाली नगर स्थित सीरीज ज्वैल्स में हुई इस सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को दिल्ली के द्वारका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान कालवाड़ रोड स्थित देवी नगर निवासी दिग्विजय सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटे गए ज्यादातर आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपनी विदेश में पढ़ाई और पत्नी को यूके में पढ़ाने के लिए करीब 30 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया था। इसके अलावा उसने 15 लाख रुपये का पर्सनल लोन भी ले रखा था। नौकरी छूटने के बाद उसकी आमदनी बंद हो गई और वह कर्ज की किस्तें चुकाने में असमर्थ हो गया। आर्थिक दबाव बढ़ने पर उसने ज्वैलरी शोरूम में लूट की योजना बनाई। पुलिस के सामने आई इस कहानी में एक तरफ विदेश में बेहतर भविष्य बनाने की महत्वाकांक्षा है तो दूसरी तरफ कर्ज के बोझ से परेशान होकर अपराध करने का रास्ता चुनने की घटना है।

पुलिस के अनुसार, वैशाली नगर स्थित सीरीज ज्वैल्स में दिन की शुरुआत सामान्य तरीके से हुई थी। शोरूम खोलने के दौरान वहां कंसल्टेंट अंजली कायथ और सुरक्षा गार्ड महावीर प्रसाद गुप्ता मौजूद थे। इसी दौरान मास्क लगाए और सिर पर पीली टोपी पहने एक युवक शोरूम में दाखिल हुआ। शुरुआत में उसका व्यवहार सामान्य ग्राहक जैसा दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही देर में उसने चाकू निकालकर वहां मौजूद दोनों लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। अचानक चाकू देखकर शोरूम में मौजूद कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड घबरा गए। आरोपी ने उन्हें डराकर आभूषण एक बैग में भरवाए और वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गया।

लूटे गए आभूषणों में सात हीरे, सोने का एक हार और 31 अंगूठियां शामिल थीं। इनकी कुल कीमत करीब 37 लाख रुपये बताई गई है। वारदात के बाद शोरूम में मौजूद कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। दिनदहाड़े ज्वैलरी शोरूम में चाकू की नोक पर हुई लूट की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शोरूम में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के मुताबिक, शोरूम की कंसल्टेंट अंजली कायथ की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी की पहचान और उसके भागने के रास्ते का पता लगाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने वारदात के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए पहले से ही सावधानी बरती थी। शोरूम से निकलने के बाद वह एक सुनसान गली में पहुंचा और वहां अपने कपड़े बदल लिए। इस तरह उसने वारदात के समय पहने कपड़ों के आधार पर पहचान होने की आशंका को कम करने की कोशिश की। कपड़े बदलने के बाद वह स्कूटी से कालवाड़ रोड स्थित अपने घर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने घटना के बाद सामान्य स्थिति बनाए रखने और संदेह से बचने का प्रयास किया। हालांकि, पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही थी और उसके आने-जाने के रास्तों तथा गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही थी।

पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के बाद आरोपी ने लूटे गए आभूषणों को बेचने की योजना बनाई। इसके लिए वह जयपुर से दिल्ली चला गया। उसकी पत्नी भी दिल्ली में रह रही थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी वहां लूटे गए गहनों को बेचने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसकी तलाश पूरी कर ली। तकनीकी और अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे दिल्ली के द्वारका इलाके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से लूटे गए ज्यादातर आभूषण बरामद कर लिए। बरामदगी के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि लूटे गए सभी गहने उसके पास ही थे या उसने कुछ आभूषणों को कहीं और रखने अथवा बेचने की कोशिश की थी। पूछताछ में दिग्विजय सिंह ने अपनी आर्थिक परेशानी को वारदात की वजह बताया।

उपग्रह संचार पर भारत का हो पूरा नियंत्रण, नेटवर्क बंद करने का अधिकार भी देश के पास रहे

नई दिल्ली। अंतरिक्ष और संचार तकनीक के तेजी से बदलते दौर में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारती एयरटेल के संस्थापक एवं चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि भारत में संचालित होने वाली उपग्रह संचार सेवाओं को बंद करने या उनकी गति सीमित करने का अधिकार पूरी तरह देश के पास होना चाहिए। किसी विदेशी कंपनी या दूसरे देश के पास यह नियंत्रण नहीं होना चाहिए कि वह अपनी इच्छा से भारत में काम कर रहे उपग्रह नेटवर्क को बंद कर दे। मित्तल ने इस अधिकार को 'किल स्विच' की संज्ञा देते हुए कहा कि भारत को अपने अंतरिक्ष भविष्य, संचार व्यवस्था और महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। उनके मुताबिक, आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप में उपग्रह संचार केवल इंटरनेट या दूरसंचार की सुविधा नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक संप्रभुता का अहम हिस्सा बन चुका है।

भारती एंटरप्राइजेज के 50 साल पूरे होने के अवसर पर पीटीआई-भाषा को दिए साक्षात्कार में मित्तल ने कहा कि भारत को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिसमें देश के भीतर संचालित होने वाली उपग्रह सेवाओं पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भारतीय संस्थाओं के पास रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संचार व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्सों को किसी एक विदेशी कंपनी या देश के नियंत्रण में छोड़ना भविष्य में जोखिम पैदा कर सकता है। आज के समय में किसी देश की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं और सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है। संचार नेटवर्क, डिजिटल ढांचा, अंतरिक्ष आधारित तकनीक और डेटा का निर्बाध प्रवाह भी सुरक्षा रणनीति के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। मित्तल ने ड्रोन, साइबर अभियान और निर्देशित मिसाइलों के बढ़ते इस्तेमाल का उल्लेख करते हुए कहा कि युद्ध की परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। ऐसे समय में उपग्रह संचार नेटवर्क की भूमिका लगातार बढ़ रही है। सैन्य गतिविधियों, निगरानी, आपातकालीन संपर्क और रणनीतिक सूचनाओं के आदान-प्रदान में इन नेटवर्कों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि किसी संकट या युद्ध जैसी स्थिति में किसी विदेशी कंपनी के नियंत्रण वाला उपग्रह नेटवर्क अचानक बंद हो जाए या उसकी सेवाएं सीमित कर दी जाएं, तो इससे देश की महत्वपूर्ण संचार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत के पास सेवाओं को नियंत्रित करने और आवश्यकता पड़ने पर बंद करने का अधिकार होने की आवश्यकता बताई।

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब भारत का उपग्रह संचार बाजार नई प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रवेश कर रहा है। एलन मस्क की स्टारलिंक, भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब और रिलायंस की जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस जैसी कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। इन कंपनियों की तकनीक दूरदराज के क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों, समुद्री क्षेत्रों और ऐसे स्थानों तक इंटरनेट पहुंचाने में मदद कर सकती है, जहां पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क या फाइबर आधारित कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना मुश्किल होता है। हालांकि, इन सेवाओं के विस्तार के साथ सुरक्षा, नियंत्रण, स्पेक्ट्रम प्रबंधन और नियामकीय निगरानी से जुड़े सवाल भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

मित्तल ने यूटेलसैट वनवेब की तैयारियों का जिक्र करते हुए बताया कि कंपनी का जमीनी बुनियादी ढांचा पिछले तीन वर्षों से तैयार है। इसके उपग्रह करीब पांच वर्षों से भारत के ऊपर से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद कंपनी को देश में वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने संकेत दिया कि उपग्रह नेटवर्क के संचालन के लिए केवल अंतरिक्ष में उपग्रहों की मौजूदगी और जमीन पर आवश्यक ढांचे का तैयार होना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सरकार की ओर से निर्धारित सभी नियामकीय और सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करना जरूरी है।

उपग्रह संचार सेवाओं के संचालन को लेकर मित्तल ने लाइसेंस और वास्तविक परिचालन अनुमति के बीच अंतर भी स्पष्ट किया। उनके मुताबिक, किसी कंपनी को सेवा देने का लाइसेंस मिल जाना अपने आप में वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की अनुमति नहीं माना जा सकता। कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन, सुरक्षा संबंधी शर्तों और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुरूप व्यवस्था तैयार होने के बाद ही सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। यह व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपग्रह संचार का इस्तेमाल आम नागरिकों के इंटरनेट से लेकर सरकारी और रणनीतिक संचार तक विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है। भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं को लेकर कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से दूरसंचार क्षेत्र में नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क की पहुंच से बाहर रहने वाले गांवों, सीमावर्ती इलाकों, द्वीपों और दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में उपग्रह इंटरनेट उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा आपदा के समय जब मोबाइल टावर या जमीन आधारित संचार व्यवस्था प्रभावित हो जाती है, तब उपग्रह नेटवर्क संपर्क बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। विमानन, समुद्री परिवहन, रक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों में भी इन सेवाओं की उपयोगिता बढ़ रही है। लेकिन इन संभावनाओं के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि देश की सुरक्षा से जुड़े संचार संसाधनों पर पर्याप्त नियामकीय निगरानी और नियंत्रण बना रहे।

मित्तल ने अपने विचारों के समर्थन में यूक्रेन युद्ध का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि वहां स्टारलिंक और वनवेब जैसी उपग्रह सेवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। इस संघर्ष ने दुनिया को यह दिखाया है कि आधुनिक युद्ध में उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। युद्ध के दौरान जमीन पर मौजूद संचार ढांचे को नुकसान पहुंचने या उसके काम नहीं करने की स्थिति में अंतरिक्ष आधारित नेटवर्क संपर्क बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। इससे सैन्य और रणनीतिक गतिविधियों में उनकी उपयोगिता सामने आई है। साथ ही यह सवाल भी महत्वपूर्ण हुआ है कि ऐसे नेटवर्क का नियंत्रण किसके हाथ में होना चाहिए और किसी आपात स्थिति में उनकी सेवाओं को लेकर अंतिम फैसला कौन करेगा।

पश्चिम रेलवे ने दिवाली-छठ पर्व की भीड़ के दौरान उधना स्टेशन पर लगभग 2.70 लाख यात्रियों का किया सफलतापूर्वक प्रबंधन

पश्चिम रेलवे ने त्योहारी भीड़ के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 1 से 10 नवंबर, 2026 तक 73 लाख यात्रियों की आवाजाही का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया। यह पिछले वर्ष के दिवाली त्योहारी सीजन की तुलना में 2 लाख यात्रियों की वृद्धि को दर्शाता है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दिवाली-छठ पर्व की भारी भीड़ के दौरान 1 से 10 नवंबर तक 10 दिनों में अकेले उधना स्टेशन पर लगभग 2.70 लाख यात्रियों का प्रबंधन किया गया और स्पेशल ट्रेनों के 250 से अधिक फेरे चलाए गए। यात्री यातायात में इस अभूतपूर्व वृद्धि के बावजूद, पश्चिम रेलवे ने सावधानीपूर्वक योजना, भीड़ प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था और उधना स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के माध्यम से यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की।

दिवाली से पहले के तीन दिनों के दौरान उधना स्टेशन पर कुल 111 ट्रेनों का प्रबंधन किया गया, जिसमें इस स्टेशन से आरंभ होने वाली 27 नियमित और 19 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। उत्कृष्ट परिचालन दक्षता का प्रदर्शन करते हुए, उधना स्टेशन ने 7/8 नवंबर, 2026 की रात को मात्र 15 घंटे की अवधि में 45,000 से अधिक यात्रियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया।







रियल टाइम के आधार पर स्थिति की कड़ी निगरानी की जा रही थी और उसी के अनुसार, यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों को भी अधिसूचित किया गया।

इसके अतिरिक्त, सूरत और उधना स्टेशनों पर यात्रियों का भार कम करने के लिए उत्राण स्टेशन को सूरत के एक नए सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां से विभिन्न गंतव्यों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और बड़ा कदम बांद्रा टर्मिनस, उधना, सूरत, उत्राण, वडोदरा, अहमदाबाद और साबरमती रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर होल्डिंग एरिया स्थापित करना रहा। निर्बाध यात्रा की सुविधा प्रदान करने और प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए, चौबीसों घंटे टिकटिंग की व्यापक व्यवस्था की गई, जिसमें अतिरिक्त बुकिंग काउंटर, ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनें (ATVMs) और मोबाइल यूटीएस (M-UTS) कर्मचारी शामिल थे। यात्रियों का मार्गदर्शन करने और उन्हें सुव्यवस्थित तरीके से ट्रेन में चढ़ने में मदद करने के लिए टिकट चेकिंग कर्मचारियों को तैनात किया गया था। इसके साथ ही, व्यवस्था बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF), राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) और स्थानीय पुलिस को भी तैनात किया गया था।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 10,000 वर्ग मीटर से अधिक में फैला उधना का यात्री सुविधा केंद्र 31 अक्टूबर 2026 को शुरू किया गया था और यह भारत का सबसे बड़ा यात्री होल्डिंग एरिया है, जिसमें एक समय में 15,000 से अधिक यात्रियों को ठहराने की क्षमता है। इसे यात्रियों को एक सुरक्षित, आरामदायक और व्यवस्थित प्रतीक्षा स्थल प्रदान करने के लिए हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं की तर्ज पर विकसित किया गया है। इस कवर्ड वेटिंग एरिया (प्रतीक्षा स्थल) में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था, 10 समर्पित टिकट-बुकिंग काउंटर के साथ-साथ पुरुष, महिला और दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाएं और शिशु आहार कक्ष (बेबी फीडिंग रूम) भी शामिल हैं। यह सुविधा केंद्र व्यापक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है, जिनमें RO-फिल्टर्ड पेयजल वाले वॉटर कूलर, 32 हाई वॉल्यूम लो स्पीड (HVLS) पंखे, 146 स्पीकरों वाला पब्लिक एड्रेस (PA) सिस्टम, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड, बेहतर निगरानी के लिए 55 एआई (AI) आधारित हाई-एंड सीसीटीवी कैमरे, निरंतर निगरानी के लिए वॉर रूम, बेहतर साइनेज के साथ-साथ अग्नि-सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन के प्रावधान शामिल हैं।

यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए, पश्चिम रेलवे ने दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन के दौरान नियमित ट्रेनों के अलावा हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों के 2,000 से अधिक फेरे संचालित किए। कर्मचारियों की व्यापक तैनाती और वास्तविक समय (रियल-टाइम) में ट्रेनों के परिचालन से त्योहारी सीजन के दौरान घर लौटने वाले लाखों यात्रियों के लिए सुरक्षित, अनुशासित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित हुई। बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण त्योहारी भीड़ का यह सफल प्रबंधन, यात्री सुरक्षा, सुविधा और कुशल भीड़ प्रबंधन के प्रति पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

निर्यात में भारत की ऊंची उड़ान, अक्टूबर में 30 प्रतिशत की ऐतिहासिक बढ़त

नई दिल्ली। वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देश की मजबूत होती स्थिति के बीच अक्टूबर में भारत के निर्यात ने शानदार प्रदर्शन किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में देश का कुल निर्यात पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 29.9 फीसदी बढ़कर 89.99 अरब डॉलर पहुंच गया। अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 69.27 अरब डॉलर था। निर्यात में लगभग 30 फीसदी की यह वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उत्साहजनक संकेत मानी जा रही है। खास बात यह है कि निर्यात में तेजी के साथ देश के व्यापार घाटे में भी कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में देश का आयात भी बढ़ा और यह 110.07 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी महीने आयात 94.42 अरब डॉलर था। इस तरह आयात में करीब 15.65 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, निर्यात की तेज रफ्तार के कारण व्यापार घाटे की स्थिति में सुधार देखने को मिला। अक्टूबर में व्यापार घाटा घटकर 20.09 अरब डॉलर रह गया, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 25.15 अरब डॉलर था। यानी एक साल के भीतर व्यापार घाटे में लगभग पांच अरब डॉलर की कमी आई है। निर्यात में वृद्धि और व्यापार घाटे में गिरावट को देश के बाहरी व्यापार संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अक्टूबर के दौरान निर्यात में आई मजबूती के पीछे कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का बेहतर प्रदर्शन रहा। विशेष रूप से रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और रसायन जैसे क्षेत्रों ने निर्यात वृद्धि में अहम योगदान दिया। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से अक्टूबर के बीच रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 40.06 फीसदी बढ़